Karnataka, Maharashtra & Goa, Punjab, Rajasthan and West Bengal are accredited by UGC.

(c) Yes, Sir.

(d) The standard of State level Eligibility Tests is monitored by UGC with the help of its Committee on Accreditation of Tests.

कृषि क्षेत्र हेतु विश्व बैंक की सहायता

583. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री इकबाल सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या विश्व बैंक देश में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य, विशेषकर पंजाब को प्रदान की गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों ने इस संबंध में प्राप्त की गई धनराशि का पूर्णत: उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई इस प्रकार की सहायता का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है [देखिये परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 20] गत तीन वर्षों में पंजाब को दी गई सहायता इस प्रकार है:–

(रुपए लाख में)

परियोजना का नाम	वर्ष 1993-94	1994-95	1995-96
1. समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाड़ी)	896.05	1288.37	1029.45
2. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-2	72.34	81.73	31.00
3. राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-3	3268.40	2643.50	

(ग) जी, हां, चूंकि विश्व बैंक द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है।

(घ) भाग (ख) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ही।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

Banning the Use of Polythene Bags

584. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state: (a) whether attention of Government has been drawn to the news-item appearing in the 'Statesman' dated the 5th June, 1996, captioned "Slow poisoning via polythene bags";

(b) if so, whether the use of polythene bags is causing various types of diseases;

(c) whether the use of polythene in advanced countries has been banned and these countries are dumping their wastes in India; and

(d) if so, the steps Government propose to take to ban the use of polythene?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) Yes, Sir.

(b) Polythene bags are not harmful to the environment per sec. Plastic bags or other plastic packaging should have food grade pigments, plasticizers and additives (other chemicals), these do not lead to any harmful effects.

(c) and (d) Based on available information, the use of polythene bags in advanced countries is not banned. As per the amended Export-Import Policy (1992—1997), the import of plastic waste is included in the restricted list and its import is permitted against a licence.

रेल लाइन का परिवर्तन

585. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या रेल मंत्री 7 मार्च, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 115 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दरभंगा-निरमली, दरभंगा-जयनगर, दरभंगा-नरकटियागंज और झंझारपुर-लोकहा मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने से संबंधित सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या भारत-नेपाल सीमा पर स्थित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रेल लाइनें बिछाने से संबंधित कार्य वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान आरंभ हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी हां, सकरी से हसनपुर रोड तक नई लाइन का निर्माण कार्य 100 करोड़ रुपये की लागत पर बजट में शामिल कर लिया गया है। इस लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य वित्त वर्ष 1996-97 में शुरू किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का बिछाया जाना

586. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस.एस. सुरजेवाला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 से आज की तिथि तक मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नयी रेल लाइनें बिछाई गई हैं;

(ख) राज्य में ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस समय नयी रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं;

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान रेल सेवाओं के विस्तार और सुधार से संबंधित कार्य तथा रेल लाइनों को बिछाने से संबंधित किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) मध्य प्रदेश में 1995 से कोई नई लाइन नहीं बिछाई गई है, बहरहाल, परसिया-छिंदवाड़ा का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है।

(ख) इस समय देवास-मक्सी तथा गुना-इटावा खण्डों में कार्य प्रगति पर है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) में रेल लाइन बिछाने से संबंधित का विवरण दिया गया है, मध्य प्रदेश में गाड़ी सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के बारे में यह उल्लेखनीय है कि :-

(i) यात्रियों को यथा संभव कम से कम समय में टिकट जारी करना सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश के कुछ स्टेशनों पर माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित स्वत: मुद्रण टिकट मशीनें लगायी गई हैं।

(ii) रेलवे स्टेशनों का विस्तार तथा सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है, मध्य प्रदेश राज्य के कुछ स्टेशनों पर 1995-96 के दौरान प्रतीक्षा कक्षों/प्रतीक्षालयों, प्लेटफार्म सायवानों, पीने के पानी की सुविधाओं, बैठने के स्थान की व्यवस्था आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था इनमें वृद्धि करने से संबंधित यथापेक्षित कार्य किए गए थे।

(iii) 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित गाड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:-

1. नई गाड़ियां

8403/8404	पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
4243/4244	सूरत-वाराणसी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
1517/1518	सतना-मानिकपुर पैसेन्जर
1519/1520	सतना-मानिकपुर पैसेन्जर
1 पी.बी./ 2 पी.बी.	बिलासपुर-पांडरा रोड पैसन्जर
4313/4314	दादर-बरेली एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
1029/1030	पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
7611/7612	नांदेड-अमृतसर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
1031/1032	पुणे-वाराणसी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
1 आर.बी./ 2 आर.बी.	बिलासपुर-रायपुर पैसेन्जर
33/34	नीमच-चित्तौड़गढ़ पैसेन्जर
69/70	इंदौर-मऊ पैसेन्जर
9303/9304	इंदौर-भोपाल डी.एम.यू. गाड़ी

Banning the use of Polythene Bags

587. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that polythene bags are not bio-degradable and, therefor a cause of environmental degradation;

(b) whether it is also a fact that under the public awareness campaign of Bharat Vikas Parishad, Manali Town Himachal Pradesh has completely replaced polythene bags by paper and jute bags; and

(c) whether Government would consider adivising all States to follow this healthy example and ban the use of polythene bags in their respective territories?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD